

राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

जयपुर, दिनांक: ०९-१०-२३

एफ ३.१(१)प्रथम/निर्वा/२०२३/६१८६

प्रेषक : मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषिति : मुख्य सचिव
राजस्थान सरकार
जयपुर।

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/
शासन सचिव
राजस्थान सरकार

: राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी,
(NIC) सचिवालय, जयपुर।

समस्त अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/निदेशक/सचिव
बोर्ड/आयोग/निगम राजस्थान

: सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार
विभाग राजस्थान, जयपुर।

समस्त संभागीय आयुक्त,
राजस्थान।

विषय : विधानसभा आम चुनाव, २०२३ – आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों की पालना
बाबत।

प्रसंग : भारत निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक ४३७/६/१/ECI/INST/FUNCT/MCC/२०२३
दिनांक ०९ अक्टूबर २०२३, ४३७/६/INST/२०१५-CCS दिनांक २९ दिसम्बर, २०१५,
४३७/६/INST/२०१२-CC&BE दिनांक १८ जनवरी, २०१२, ३/७/२००८ JS-II दिनांक
७ अक्टूबर, २००८, ४३७/६/१/२०१४-CC&BE दिनांक ५ मार्च, २०१४, ४३७/६/INST/२०१४-
CC&BE दिनांक २० मार्च, २०१४ एवं ४६४/INST/२०१४/EPS दिनांक १० अप्रैल २०१४

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम चुनाव, २०२३ के कार्यक्रम की घोषणा दिनांक ०९ अक्टूबर, २०२३ को की जा चुकी है। कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही सम्पूर्ण राज्य में आदर्श आचार संहिता प्रभाव में आ चुकी है तथा निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक प्रभावी रहेगी। आचार संहिता प्रभाव में रहने के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निम्न निर्देश दिये गये हैं:-


1. **सम्पत्ति का विरूपण:** आयोग के प्रासंगिक पत्र दिनांक ०७.१०.२००८, १८.०१.२०१२ एवं २९.१२.२०१५ (प्रतियों संलग्न) में दिये गये दिशानिर्देशों के अनुसार सम्पत्ति के विरूपण के रोकथाम का प्रावधान है। आयोग ने अपने अनुदेशों का सक्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने तथा समयबद्ध कार्यवाही करने के लिए निम्नलिखित निर्देश दिये हैं।
 - A- **सरकारी सम्पत्ति का विरूपण:-** सरकारी सम्पत्ति पर सभी प्रकार के दीवार लेखन, पोस्टर/पेपर या किसी अन्य रूप में विरूपण, कटआउट/होर्डिंग, बैनर, झंडा आदि को निर्वाचन की घोषणा से **२४ घण्टे के भीतर** हटा दिये जायेंगे। संलग्न-प्रपत्र-१
 - B- **सार्वजनिक सम्पत्ति का विरूपण तथा सार्वजनिक स्थान का दुरुपयोग:** सार्वजनिक सम्पत्ति तथा सार्वजनिक स्थान जैसे रेल्वे स्टेशन, बस अड्डा, हवाई अड्डा, पुल, रोडवेज, सरकारी बस, बिजली/टेलीफोन का खंभा, स्थानीय निकाय का भवन आदि में दीवार लेखन/पोस्टर/पेपर के रूप में सभी अप्राधिकृत राजनीतिक विज्ञापन या किसी अन्य रूप में विरूपण, कटआउट/होर्डिंग, बैनर, झंडा आदि को आयोग द्वारा निर्वाचनों की घोषणा से **४८ घंटे के अन्दर** हटा दिए जाएंगे। संलग्न-प्रपत्र-२
 - C- **निजी सम्पत्ति का विरूपण :** निजी सम्पत्ति पर प्रदर्शित सभी अप्राधिकृत राजनीतिक विज्ञापनों तथा स्थानीय विधि एवं न्यायालय के निर्देशों, यदि कोई हो, के अधीन सभी विज्ञापन आयोग द्वारा निर्वाचनों की घोषणा से **७२ घंटे के अन्दर** हटा दिए जाएंगे। संलग्न-प्रपत्र-३

2. **राजकीय वाहनों का दुरुपयोग:** आयोग के पत्र 464/INST/2014/EPS दिनांक 10 अप्रैल, 2014 (प्रति संलग्न) के द्वारा राजकीय वाहनों के दुरुपयोग के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिये गये हैं। किसी राजनैतिक दल, अभ्यर्थी या निर्वाचन से जुड़े किसी अन्य व्यक्ति द्वारा निर्वाचन के दौरान प्रचार करने, निर्वाचन प्रचार सम्बन्धी कार्य या निर्वाचन सम्बन्धित यात्रा करने के लिए सरकारी वाहन के प्रयोग पर पूरी तरह से प्रतिबन्ध होगा। आयोग के सम्बन्धित दिशा-निर्देशों की पालना निर्वाचनों की घोषणा के **24 घण्टे के अन्दर** आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। संलग्न-प्रपत्र-1
3. **सरकारी राजकोष की लागत पर विज्ञापन:** भारत निर्वाचन आयोग के प्रासंगिक पत्र दिनांक 5 मार्च, 2014 (प्रति संलग्न) द्वारा यह निर्देश दिये गये हैं कि निर्वाचनों की घोषणा के तुरन्त बाद राजकोष से सरकार की उपलब्धियों बाबत प्रिन्ट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं सोशल मीडिया में कोई भी विज्ञापन जारी नहीं किये जावें। यदि कोई विज्ञापन पूर्व में प्रकाशन हेतु जारी कर दिया है तो उसे प्रकाशित होने से तत्काल रोका जावे।
4. **विभिन्न विभागों की अधिकारिक वेबसाइट्स पर फोटो एवं सन्देश :** विभिन्न विभागों की वेबसाइट्स से मंत्री/राजनैतिक व्यक्तियों के संदर्भ/फोटो हटाये जाने के संबंध में आयोग के निर्देश क्रमांक 437/6/INST/2014-CC&BE दिनांक 20 मार्च, 2014 (प्रति संलग्न) के अनुदेश में यह प्रावधान है निर्वाचनों की घोषणा के तुरन्त बाद से केन्द्र/राज्य सरकार की अधिकारिक वेब साइट पर उपलब्ध मंत्रियों, राजनीतिज्ञों या राजनैतिक दलों के सभी संदर्भों, फोटो को तत्काल प्रभाव से हटाकर पालना सुनिश्चित करेंगे।
5. **विकास एवं निर्माण कार्यों से संबंधित गतिविधियाँ:** आदर्श आचार संहिता प्रभाव में आ जाने के कारण कोई भी नवीन कार्य प्रारम्भ नहीं हो सकता है, और साथ ही किसी भी योजना में कोई नया लाभार्थी नहीं जोड़ा जा सकता है। आपके विभाग द्वारा पूर्व से चल रहे कार्यों एवं नवीन स्वीकृत कार्य जो अभी प्रारम्भ नहीं हुए हैं, की सूची निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के **72 घण्टे की अवधि** में इस विभाग को प्रेषित करावें तथा स्थानीय स्तर पर संबंधित जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) को उपलब्ध करावें। संलग्न-प्रपत्र-4

आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित समयावधि में कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट इस विभाग को तथा जिला स्तर पर जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) को उपलब्ध करावें। आयोग के उक्त निर्देशों से आप अपने विभाग के माननीय मंत्री/राज्य मंत्री/संसदीय सचिव को पालना हेतु अवगत करावें, साथ ही अपने अधीनस्थ विभागों/स्थानीय निकायों/सार्वजनिक उपक्रमों से भी आयोग के निर्देशों की पालना कराया जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीय


(प्रवीण गुप्ता)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

एफ 3.(1)(9)प्रथम/निर्वा/2023/

जयपुर, दिनांक:

प्रतिलिपि समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर), राजस्थान को दी जाकर लेख है कि आयोग के निर्देशों की पालना कराते हुए आयोग द्वारा दी गई निर्धारित अवधि में पालना रिपोर्ट प्राप्त करें और इस विभाग को भी प्रेषित करें।

उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान, जयपुर।

INFORMATION FROM ALL DEOS RELATED TO MCC

(To be submitted upto date 19.10.2023. at 01. AM/PM)

24:00 Hours

दिनांक :

S. No.	District	Whether Defacement of Government Property Wall Writing/Posters/Papers/ Collection of Hoardings/ Banners/Flags etc. removed Yes/No	Whether use of official Vehicle by Prohibited category Stop Yes/No	Whether Complaint Monitoring System Start Yes/No

Development/ Construction Related Activities

(To be submitted upto date 12.10.2023 at 02. AM/PM)

72:00 Hours

दिनांक :

S. No.	Name of District	Name of Department/ Agency	Number/List of works which has already been started on ground before implementation of MCC	Number/List of fresh works which has not started on ground before implementation of MCC

By Speed Post/E-mail

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NIRVACHAN SADAN, ASHOKA ROAD, NEW DELHI-110001

No. 437/6/1/ECI/INST/FUNCT/MCC/2023

Dated: 9th October, 2023

To

1. The Cabinet Secretary,
Government of India,
Rashtrapati Bhawan,
New Delhi.
2. The Chief Secretaries to the Government of :-
 - (i) Chhattisgarh, Raipur ;
 - (ii) Madhya Pradesh, Bhopal ;
 - (iii) Mizoram, Aizawl ;
 - (iv) Rajasthan, Jaipur ; and
 - (v) Telangana, Hyderabad.
3. The Chief Electoral Officers of :-
 - (i) Chhattisgarh, Raipur;
 - (ii) Madhya Pradesh, Bhopal;
 - (iii) Mizoram, Aizawl;
 - (iv) Rajasthan, Jaipur ; and
 - (v) Telangana, Hyderabad.

Subject: Immediate action to be taken for enforcement of Model Code of Conduct after announcement of General Elections to State Legislative Assemblies of Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Mizoram, Rajasthan and Telangana , 2023 - regarding.

Sir,

I am directed to state that the Election Commission has announced the schedule for holding General Elections to State Legislative Assemblies of **Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Mizoram, Rajasthan and Telangana**, operation of 'MODEL CODE OF CONDUCT' comes into effect with the announcement of elections by the Commission. In view of the general election to the Legislative Assemblies of Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Mizoram, Rajasthan and Telangana, 2023, the Commission has given following directions for effective enforcement of provisions of MCC:-

1. **Defacement of Property-** ECI instructions contained in letters, No. 437/6/INST/2015-CCS, dated 29th December, 2015, No. 437/6/INST/2012- CC&BE dated 18th January, 2012 and No. 3/7/2008 JS-II dated 7th October, 2008 , provide for prevention of defacement of property. The Commission has directed to ensure strict compliance of its instructions and to take time bound action as prescribed below-

(a) **Defacement of Government property-** For this purpose a Government premise would include any Government office and the campus wherein the office building is situated. All wall writing, posters/papers or defacement in any other form, cutout/hoardings, banners, flags etc, on Government property shall be removed **within 24 hours** from the announcement of elections

(b) **Defacement of public property and misuse of public space-** All unauthorized political advertisement, in the form of wall writing/posters/papers or defacement in any other form, cutout/hoardings, banners flags etc. at public property and in public space like railway station, Bus stands, Airports, railway Bridges, Roadways, Govt. Buses, Electric/Telephone poles , municipal/local bodies' buildings etc., shall be removed **within 48 hours** from the announcement of elections by the Commission.

(c) **Defacement of private property-** All unauthorized political advertisement displayed at private property and subject to local law and court's directions, if any, shall be removed **within 72 hours** from the announcement of elections by the Commission.

2. **Misuse of official vehicle-** The ECI's Consolidated instructions contained in letter No. 464/L&O/2023/EPS(Use of Veh.), dated 26th June 2023, among other things, provides that **there shall be a total ban on use of official vehicle by any political party, candidate or any other person connected with election (except officials performing any election related official duty) for campaigning, electioneering or election related travel during elections (subject to certain exception mentioned therein).** The expression official vehicle means and shall include , any vehicle used or capable of being used for the purpose of transport, whether propelled by mechanical power or otherwise and will include trucks, lorries, tempos, jeeps, cars, auto rickshaws, e-rickshaws, buses, belonging to Central Government, State Government/UT Administrations, public undertakings of Central/State Government, Joint sector undertakings of Central/State Government, local bodies, municipal corporations, marketing boards, cooperative societies or any other body in which public funds , however small a portion of the total, are invested. **The CEOs/DEOs shall take necessary action for compliance of ECI instructions within 24 hrs of the announcement of the elections.**

3. **Advertisement at the cost of public exchequer-** ECI instructions contained in letters, No. 437/6/1/2014-CC&BE, dated 5th March, 2014 provides that at the cost of public exchequer in the newspapers and other media and the misuse of official mass media during the election period for partisan coverage of political news and publicity regarding achievements with a view to furthering the prospects of the party in power shall be scrupulously avoided. No advertisements shall be issued in electronic and print media highlighting the achievements of the Govt. at the cost of public exchequer. If any advertisement has already been released for

telecast/broadcast or publication in the print media, it must be ensured that the telecast/broadcast of such ads on electronic media is stopped forthwith and that no such ad is published in any newspapers, magazines, etc., i.e. in print media, from the date of announcement and it should be immediately withdrawn. **The CEOs/DEOs has to take immediate action to remove/stop any advertisement, in the print/electronic media, showing the achievements of the Government soon after the announcement of elections.**

4. **Photograph of political functionary at official website-** ECI instruction contained in letter No. 437/6/INST/2014-CC&BE dated 20th March, 2014 provides that all references of Ministers, Politicians or political parties available on central/state Government's official website, shall be removed. The CEOs have to take **immediate action** to remove/hide the photographs of any political functionary from official websites of state department.
5. **Development/construction related activities- within 72 hours** of announcement of elections, the CEO/DEO shall obtain the following list of works for reference in case of validating any complaint on violation of MCC:
 - (i) List of work which has already been started on ground.
 - (ii) List of fresh work which has not started on ground.
6. **Activities for Expenditure Monitoring and enforcement of MCC-** Flying squad, FST, video team, intensive checking for liquor/Cash/Contra banned drugs, flying squads of excise department to check illicit trafficking of Drug/Narcotics to be **immediately activated** after announcement.
7. **Complaint Monitoring System-** The poll going states shall have a complaint redressal mechanism based on website and call center. The toll free number of call center is 1950. Complaints can be registered by making calls to the toll free call center numbers or on the web site. Complainants will also be informed of the action taken by SMS and by the call center. Complainants can also see the details of the action taken on their complaints. This system should be **operational within 24 hours** of the announcement. All complaint should be dealt with promptly and properly. The 24x7 control Room at the district level must be activated and sufficient deployment of manpower and other logistics be ensured in particular, round the clock personnel should be deployed in the control room and their duty roster must be issued to avoid any evasion or confusion.
8. **IT Application-** All IT applications including official website and social media shall be **operational with the announcement**.
9. **Dissemination of information for Awareness of Voters and political parties.** Publicity of major election activity would be given through CEO/DEO/RO. For this purpose, all necessary

information shall be disseminated through radio, tv, cinema. Government channel to display voter education material.

10. **Active cooperation from Educational Institution and Civil Societies-** Cooperation can be sought from educational institution and civil societies for giving wide publicity to the election related information to the general public and other stakeholders.
11. **Media Centre-** Effort should be made for awareness among the voters, political parties and other stakeholder through media center about election system including use of EVM/VVPAT.
12. **MCMC/DEMC-** ECI instruction contained in letter no. 491/MCMC/2014/Communication dated 24th March, 2014 provides that all registered political parties will approach the Media Certification and Monitoring Committees (MCMC) at District and State level, as the case may be, for pre-certification of their political advertisements proposed to be issued on electronic media. The Commission has directed to ensure strict compliance of its instructions contained in above said letter.
13. **Control Room-** The 24x7 control room at district level must be activated immediately and sufficient deployment of manpower and other logistics be ensured by the DEO/CEO. A control room with complaint Monitoring Centre would also be set up at ECI Secretariat during the entire election process.
14. Hindi version will follow.

Yours faithfully



(ASHWANI KUMAR MOHAL)
SECRETARY